RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 22 MAY TO 28 MAY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 35 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

ई-कॉमर्स कंपनियों को शेयर्ड वेयरहाउस को कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन

Page 3

नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पसंदीदा है रम दक्षिण भारत में बीयर का कल्चर है

Page 4

विकसित भारत की दिशा में बढ़े कदम, बेहतर हो रही जिंदगी

Page 7

editoria!

नयी पीढी की उम्मीदें

भारत समेत दुनियाभर में नयी पीढ़ी को ऐसे संसाधन मिले हैं, वे पहले की पीढ़ियों को उपलब्ध नहीं थे. पर किशोरों और युवाओं को ऐसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो बिल्कुल नयी हैं. जलवायु परिवर्तन एक ऐसी ही गंभीर समस्या है. इसके अलावा शिक्षा एवं कौशल, रोजगार, यौन शोषण, स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति से संबंधित चिंताएं भी हैं, जिनसे हर पीढ़ी को जूझना पड़ता है. संतोषजनक बात यह है कि नयी पीढ़ी समस्याओं से परिचित भी है और उनके समाधान के लिए प्रेरित भी. डेलॉयट के जेन-जी और मिलेनियल पीढ़ी के ताजा सर्वेक्षण से यही संकेत निकलते हैं. आम तौर पर 1981 और 1996 के बीच जन्मे लोगों को मिलेनियल या जेन वाई तथा उसके बाद की पीढ़ी को जेन-जी (जेड) की संज्ञा दी जाती है. इन दो पीढ़ियों के अंतर्गत वर्तमान के सभी किशोर और युवा आ जाते हैं. इस सर्वेक्षण में 44 देशों के लगभग 23 हजार लोगों की राय ली गयी, जिनमें से करीब आठ सौ भारतीय हैं. आबादी के अनुपात में सर्वेक्षण का यह आंकड़ा बहुत कम है, पर इससे नयी पीढ़ी के सोच का एक आकलन अवश्य मिलता है. अक्सर ऐसे सर्वेक्षण शहरी क्षेत्र के उच्च और उच्च मध्यम आय वर्ग तक सीमित रहते हैं. इस पहलू का ध्यान रखते हुए आज के सोशल मीडिया, सूचना तंत्र तथा आकांक्षाओं के व्यापक विस्तार के दौर में इस सर्वेक्षण को नयी पीढ़ी की राय का समुचित प्रतिबिंब माना जा सकता है.. भारतीय जेन-जी पीढ़ी की चिंताओं के केंद्र में शिक्षा, कौशल एवं प्रशिक्षण, रोजगार, जलवायु परिवर्तन, यौन शोषण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय हैं. मिलेनियल पीढ़ी भी कमोबेश इन्हीं विषयों को महत्वपूर्ण मानती है. एक उत्साहजनक तथ्य यह सामने आया है कि दोनों पीढ़ियों में अधिकतर लोगों को उम्मीद है कि आगामी एक वर्ष में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य बेहतर होगा. युवा पीढ़ी अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तरह रोजगार को केवल आमदनी का जरिया नहीं मानती है, बल्कि उसके लिए अपने काम से संतोष मिलना और काम का उद्देश्यपरक होना भी महत्वपूर्ण है. यह पीढ़ी यह भी चाहती है कि उसके काम से पर्यावरण पर कम-से-कम नकारात्मक असर पड़े. हालांकि वैश्विक स्तर पर इन दोनों पीढ़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हिचक का भाव है, पर भारतीय युवा इस तकनीकी विशिष्टता को अपनाने के लिए उत्सुक है. हमारी सरकारों, उद्योग जगत, शिक्षण संस्थानों तथा समाज को नयी पीढ़ी द्वारा इस सर्वेक्षण में अभिव्यक्त आकांक्षाओं एवं आशंकाओं का समुचित संज्ञान लेना चाहिए.

शेयर मार्केट में बड़ा उछाल, पहली बार मार्केट वैल्यू 5 ट्रिलियन के पार

आईपीटी नेटवर्क

भारतीय शेयर मार्केट (share market) ने एक बार फिर माइलस्टोन छुआ है। पहली बार बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन (BSE Market Cap) 5 ट्रिलियन डॉलर (5 trillion dollar) के पार चला गया है। ए पर लिस्टेड स्टॉक्स के मार्केट कैप 414.62 लाख करोड़ रुपये पर क्लोज हुए है। इससे पहले 29 नवंबर 2023 को पहली बार भारतीय शेयर बाजार का वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर पार किया था। महज छह महीने में भारतीय शेयर बाजार के मार्केट वैल्यू में एक ट्रिलियन डॉलर का बड़ा उछाल आया है।

मार्केट कैप की नई ऊंचाई

मंगलवार (21 मई) को मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक्स में खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 414.62 लाख करोड़ रुपये पट क्लोज हुआ है। इसी के साथ डॉलट टर्म्स में भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट केप 5 ट्रिलियन डॉलर के पाट जाने में कामयाब रहा। हालांकि बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (nifti) अभी भी अपने लाइफटाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा था

मोदी-शाह के बयान ने भरा जोश

शेयर बाजार में लगातार और तेजी से उछाल आ रहा है। यह सामान्य नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बयानों को इसकी वजह माना जा रहा है। 13 मई 2024 को गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार के नए हाई तो छूने के संकेत दिए थे। साथ ही गृह मंत्री ने लोगों को निवेश की सलाह भी दी थी।

जिस उड़ान का लंबे समय से था इंतजार, उसके करीब पहुंची देश की इकॉनमी

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मई 2024 के लिए जारी अपने मंथली बुलेटिन में कहा है कि लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे हैं कि भारतीय इकॉनमी टेकऑफ करने वाली है। आंकड़े बता रहे हैं डिमांड में जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। ग्रामीण इलाकों में नॉन-फूड चीजों पर खर्च बढ़ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के खर्च करने की प्रवृत्ति में सुधार हो रहा है। लेख में कहा गया है कि भारत में गरीबी और अत्यधिक अभाव जैसी पुरानी अवधारणाएं विलुप्त होने को हैं। घरेलू मांग में निरंतर तेजी और कामकाजी उम्र की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए लेख में कहा गया है कि, 'इटरनैशनल लेवल पर यह आशावाद बढ़ रहा है कि भारत आर्थिक प्रगति के शिखर पर है।' बुलेटिन में कहा कि भारत में डिमांड मोमेंटम बढ़ रहा है। ग्रामीण खर्च में सुधार के कारण कुल नॉन-फूड खर्च बढ़ रहा है। कम से कम दो वर्षों में पहली बार पिछली तिमाही में डेली यूज की उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) की गांवों में मांग शहरी बाजारों से आगे निकल गई है। घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पादों की मजबूत मांग से FMCG वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही। इस वृद्धि को 7.6 प्रतिशत की ग्रामीण वृद्धि से गति मिली। वहीं शहरी क्षेत्रों में वृद्धि 5.7 प्रतिशत थी।

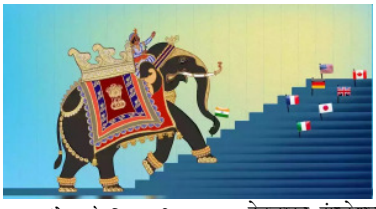

रिटेल महंगाई दर बनी रहेगी ऊंची

रिजर्व बैंक का कहना है कि दूसरी छमाही में 4% इनफ्लेशन का टारगेट हासिल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के बुलेटिन में कहा गया है, 'इस साल की दूसरी छमाही में ही इनफ्लेशन टारगेट टिकाऊ बना रह सकता है और 2025-25 के दौरान भी आंकड़ा टारगेट के आसपास रह सकता है'। बता दे कि आरबीआई हर महीने बुलेटिन जारी करता है। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा कि बुलेटिन में लिखी बातें लेखकों के विचार है।

हेडलाइन इंफ्लेशन के नीचे आने और ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद खाद्य श्रेणी में सब्जियों, अनाज, दाल, मांस और मछली की कीमतें निकट अवधि में रिटेल इंफ्लेशन को ऊंची और पांच प्रतिशत के करीब रख सकती है। यह अप्रैल में जारी अनुमान के अनुरूप है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवबत पात्रा की अगुवाई वाली टीम ने 'अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक लेख में कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए परिदृश्य नाजुक होता जा रहा है। इसका कारण एक तरफ महंगाई में जो गिरावट आ रही थी, वह अब थमती जा रही है।

'कंपनियों के रिजल्ट'

लेख में कहा गया है कि लिस्टेड कंपनियों के अबतक घोषित वित्तीय परिणाम बताते हैं कि उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना और तिमाही आधार पर रेवेन्यू में जो वृद्धि हासिल वह सर्वाधिक थी। लेख में लिखा गया है। कि हेडलाइन इंफ्लेशन में इस साल अप्रैल में मामूली कमी आई। यह हमारी उम्मीदों के अनुरूप है।

कच्चा तेल 83 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव जारी है। ब्रेंट क्रूड का मूल्य 83 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस विपणन कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया है।

ब्रेंड क्रूड में 0.57 डॉलर यानी 0.71 फीसदी की गिरावट

इस सप्ताह के तीसरे दिन शुरुआती कारोबार में ब्रेंड क्रूड 0.57 डॉलर यानी 0.71 फीसदी की गिरावट के साथ 82.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड भी 0.54 डॉलर यानी 0.68 फीसदी लुढ़ककर 79.26 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये, डीजल 87.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये, डीजल 92.15 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 103.94 रुपये, डीजल 90.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है।

लगातार दूसरे हफ्ते देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 644.151 अरब डॉलर पर पहुंचा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का विदेश मुद्रा भंडार 10 मई को समाप्त समाप्त में 2.561 अरब डॉलर बढ़कर 644.151 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार 3.67 अरब डॉलर बढ़कर 641.59 अरब डॉलर रहा था।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि 10 मई को समाप्त हफ्ते में मुद्रा भंडार का अहम घटक माने जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.49 अरब डॉलर बढ़कर 565.65 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान स्वर्ण भंडार का आरक्षित मूल्य 1.07 अरब डॉलर बढ़कर 55.95 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आरबीआई के मुताबिक विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 50 लाख डॉलर बढ़कर 18.06 अरब डॉलर हो गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के पास भारत की आरक्षित जमा 40 लाख डॉलर घटकर 4.495 अरब डॉलर रह गई है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की नजर सरकारी तेल कंपनियों पर, क्या है प्लान

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की नजर सरकारी तेल कंपनियों पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की पाइपलाइन और भंडारण (स्टोरेज) तक पहुंच चाहती है। इन पाइपलाइन और स्टोरेज का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने पिछले कई साल में किया है। इनका इस्तेमाल वे डिपो और तेल रिफाइनरी से हवाई अड्डों तक विमान ईंधन की आपूर्ति के लिए करती हैं। रिलायंस इन सुविधाओं तक पहुंच से एशिया के कुछ व्यस्त हवाई अड्डों पर ईंधन कारोबार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहती है। देश के कुल विमान ईंधन (ATF) उत्पादन में रिलायंस की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। रिलायंस दिल्ली हवाई अड्डे के बाहर के स्टोरेज डिपो के अलावा मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों तक जाने वाली पाइपलाइन तक पहुंच चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा की जाने वाली एटीएफ आपूर्ति की तुलना में फिलहाल रिलायंस की हिस्सेदारी काफी कम है।पेट्रोलियम क्षेत्र के नियामक भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने पाइपलाइन द्वारा सभी मौजूदा और भविष्य के हवाई अड्डों पर एटीएफ की आपूर्ति के बारे में नियमों के मसौदे पर टिप्पणियां मांगी है। नियामक ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और ईंधन की लागत को कम करने के लिए सभी आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति के लिए इन पाइपलाइन तक पहुंच मिलनी चाहिए। पीएनजीआरबी के मसौदे पर रिलायंस ने यह सुझाव दिया है। हालांकि, देश का ईंधन बाजार मुक्त है लेकिन देश के व्यस्त हवाई अड्डों पर एटीएफ की आपूर्ति दशकों से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा बनाई गई पाइपलाइन से की जाती है।

एटीएफ की बढ़ती डिमांड

रिलायंस एक दशक से अधिक समय से विशेष रूप से मुंबई के हवाई अड्डों पर एटीएफ की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन तक पहुंच की मांग कर रही है। कंपनी ने कहा है कि एयरलाइन के लिए पाइपलाइन के दायरे (जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्मित पाइपलाइन तक तीसरे पक्ष को पहुंच प्रदान करता है) में भंडारण सुविधाओं तथा 'ऑफ साइट' टर्मिनल सुविधाओं तक पंप स्टेशनों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एटीएफ आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रिलायंस का कहना है कि इससे यह हवाई अड्डे पर 'ऑन-साइट' भंडारण सुविधाओं के लिए एटीएफ की आपूर्ति और वितरण को एक प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित 1.71 करोड़ टन एटीएफ में से 82 लाख टन की खपत देश में होती है और बाकी का निर्यात किया जाता है। जामनगर में रिलायंस की दो रिफाइनरी करीब 50 लाख टन का उत्पादन करती हैं जिसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है। देश में विमान से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे एटीएफ की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में एटीएफ की मांग 11.8 प्रतिशत बढ़ी है।

चार जून के बाद बड़ा कदम उठाने की तैयारी में सरकार

DPIIT सेक्रेटरी ने इंडस्ट्री को दिया तैयार रहने का संकेत

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और नई सरकार बनने के बाद कई सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को उदार बनाया जा सकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील दी है और इस बात की संभावना है कि नई सरकार के सत्ता में आने पर कुछ अन्य क्षेत्रों में एफडीआई मानदंडों में राहत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कई क्षेत्रों में एफडीआई नीति को उदार बनाया है। भारत की नीतियां दुनिया में सबसे उदार एफडीआई नीतियों में से एक हैं और वास्तव में यह कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तुलना में अधिक उदार है।सिंह ने ष्छ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में कहा कि हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को आसान बनाया गया था और इस बात की बहुत संभावना है कि नई सरकार के तहत, हम जो भी क्षेत्र बचे हैं और जहां कुछ उदारीकरण संभव है, वहां इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मतगणना चार जून को होनी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2023 में भारत में एफडीआई 13 प्रतिशत घटकर 32.03 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। ऐसा मुख्य रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, ऑटो और दवा क्षेत्रों में कम निवेश के कारण हुआ।

ईवी नीति पर अच्छा रिस्पॉन्स

उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं (PLI) की सफलता के बारे में बात करते हुए सचिव ने कहा कि अब तक 1.13 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और लाभार्थी कंपनियों ने नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री, 3.45 लाख करोड़ रुपये का निर्यात सृजित किया है, और साथ ही आठ लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दी है। सिंह ने कहा कि कुछ लोग यह कहते हुए इस योजना की आलोचना करते हैं कि इससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें समय लगता है। कारोबारी सुगमता के बारे में उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के बिजनेस रेडी (बी-रेडी) सूचकांक पर काम जारी है, जिसके लिए सर्वेक्षण अगस्त में शुरू होगा।

सिंह ने कहा कि भारत को अपनी इलेक्ट्रिक-वाहन (EV) नीति पर कई ऑटोमोबाइल कंपनियों से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। यह नीति टेस्ला जैसी वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मार्च में जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि नीति में सरकार ने भारत में कोई भी वास्तविक निवेश किए बिना सिर्फ आधार स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताकर शुल्क में बदलाव करने की व्यवस्था की है। हर कोई एक कंपनी (टेस्ला) के बारे में बात करता है, लेकिन हम इस नीति पर कई कंपनियों से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं।

वर्कप्लेस को हेल्दी और कर्मचारियों के लिए अधिक बेहतर बना रही हैं कंपनियां

नई दिल्ली। एजेंसी

वर्कप्लेस में कर्मचारियों का फिट रहना सबसे अहम हैं। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय दिक्कतों को झेलने के बाद कंपनियां वर्कप्लेस को हेल्दी और कर्मचारियों के लिए अधिक बेहतर जगह बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ड्यूश बैंक, सिप्ला, अडोब, अपग्रेड, BeatO, सेक्लोर, ड्रीम स्पोर्ट्स और Ninjacart जैसी कंपनियां ऑफिस में मेडिटेशन के लिए कमरे बना रही हैं। ऑफिस में नियमित रूप से पानी और भोजन की जांच करवा रहे हैं। तेज सफेद रोशनी की जगह नेचुरल या वॉर्म एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लेकर पिछले महीने फिटनेस टक्नॉलजी कंपनी GOQii ने एक रिपोर्ट जारी किया था। इसके मुताबिक भारत की लगभग 45% आबादी अस्वस्थ होने के खतरे से जूझ रही है। इसका न केवल व्यक्तिगत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि इसे वर्कप्लेस की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है।अल्ड्रेम बैंक ने अपने कर्मचारियों को तनावपूर्ण परिस्थितियों से अलग होने या अपने मूड को नेचुरल तरीके से ठीक करने में मदद करने के लिए मेडिटेशन के कमरे बनाए हैं। जहां कर्मचारी पढ़ सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, योग या ध्यान कर सकते हैं। वहीं, Cipla ने अपने ऑफिस और प्लांट को बागानों में बदल दिया है। Cipla के ग्लोबल चीफ पीपल ऑफिसर राजू मिस्त्री ने इकॉनमिक टाइम्स को बताया कि हम समझते हैं कि आज के समय में कर्मचारियों को बहुत अधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। हमने पूरे वर्कप्लेस पर वॉर्म एलईडी लाइट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। यह न केवल एनर्जी एफिशिएंट में मदद करता है, बल्कि एक अधिक आरामदायक वातावरण भी बनाता है। यह प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिद्ध हुआ है। वहीं, Adobe ने ब्रेकआउट स्ट्रेचिंग सेशन के साथ-साथ ग्रुप एर्गोनॉमिक थेरेपी सेशंस भी शुरू किए हैं।

नेचुरल रोशनी

वर्चुअल डायबिटीज केयर प्लैटफॉर्म ष्ठ धीरे-धीरे वर्कप्लेस पर अधिक नेचुरल रोशनी को शामिल करने की ओर बढ़ रहा है। कंपनी के एचआर हेड निलाभ गुप्ता ने कहा कि हम ऐसे पौधों में भी निवेश कर रहे हैं जो हवा को शुद्ध करने और प्रदूषण को दूर करने में मदद करते हैं। इसका उद्देश्य सांस से जुड़ी दिक्कतों को कम करना है। डेटा-सेंट्रिक सिक्युरिटी सॉल्यूशन कंपनी एम्प्टी ने एक तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए ऑफिस में एक छोटा सा फिटनेस सेक्शन बनाया है। कंपनी की सीनियर डायरेक्टर श्रद्धा रेगे ने कहा कि कंपनी ने स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए ऑफिस में हेल्दी स्नैक्स और फल देना शुरू किया है। अँस एड्यू ने शारीरिक और मानसिक बेहतरी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए एक स्पोर्ट-थीम वाला वर्कप्लेस स्थापित किया है।

एडटेक कंपनी upGrad कर्मचारियों के लिए हेल्थ चेकअप, योग क्लासेज प्रदान कर रही है। जिससे वे बेहतर शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों और तनाव मुक्त जीवन जी सकें। एग्री स्टार्टअप Ninjacart ने 'बेटर लाइव्स फॉर निंजा' शुरू किया है। इसके तहत कंपनी ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, 100 कर्मचारियों के लिए फिटनेस एक्सपर्ट के निर्देशन में वजन घटाने के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

ईपीएफओ खाता धारक की मौत के बाद क्लेम के लिए आधार है जरूरी? क्या कहते हैं नए नियम

EPFO Rule Change कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम के नियमों में बदलाव किया है। ईपीएफओ ने डेथ क्लेम के नियमों में बदलाव किया है। अब डेथ क्लेम सेटल होने में समय नहीं लगेगा। नए नियम के अनुसार ईपीएफओ मेंबर के डेथ हो जाने के बाद पीएफ अकाउंट के पैसे की पेमेंट नॉमिनी को कर दी जाएगी।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में डेथ क्लेम के नियमों को बदल दिया है। इसको लेकर ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया था। ईपीएफओ के नए नियमों (EPFO New Rule) के अनुसार अगर ईपीएफओ के मेंबर की मृत्यु हो जाती है और उसका पीएफ अकाउंट (PF Account) आधार से लिंक नहीं होता है तो पीएफ अकाउंट की राशि नॉमिनी को मिल जाएगी।

ईपीएफओ के नए नियम के बाद डेथ क्लेम सेटलमेंट में कम समय लगेगा।

ईपीएफओ ने क्यों बदला नियम

ईपीएफओ ने बताया कि रीजनल अधिकारियों को आधार से लिंक करने और वेरीफाई करने में काफी समय लग रहा था और उन्हें परेशानी भी हो रही थी। इसके अलावा डेथ क्लेम सेटलमेंट (EPFO Death Claim Settlement) में भी समय लग रहा था।

ईपीएफओ के अनुसार जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके आधार में मौजूद जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब फिजिकली वेरीफाई और रीजनल ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद पीएफ अकाउंट का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। कई लोग डेथ क्लेम के जरिए फर्जीवाड़ा भी कर रहे थे। इस फर्जीवाड़ा पर नकेल कसने के लिए भी ईपीएफओ ने यह कदम उठाया है। अब कैसे होगा क्लेम सेटलमेंट नए नियम के अनुसार क्लेम सेटलमेंट से पहले नॉमिनी या फिर परिवार के सदस्य को वेरीफाई और उनकी जांच की जाएगी उसके बाद ही राशि दी जाएगी। इसके बाद ही क्लेम सेटल किया जाएगा।

यह उन स्थिति में लागू होगा जब पीएफ अकाउंट होल्डर की डिटेल्स बैंक अकाउंट से अलग होगी। अगर पीएफ मेंबर के पास गलत यूएएन होता है तब इसकी प्रक्रिया अलग होगी। वहीं पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का नाम एड नहीं होता है तो इस स्थिति में पीएफ का पैसा पीएफ मेंबर के उत्तराधिकारी को मिलेगा। इसके लिए उत्तराधिकारी को आधार कार्ड (Aadhaar Card) देना होगा।

देश की आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान: RBI

नई दिल्ली। एजेंसी

सकल मांग और गांवों में गैर-खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च बढ़ने के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मंगलवार को जारी मई बुलेटिन में यह कहा गया है। बुलेटिन में प्रकाशित 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक लेख में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाली वैश्विक बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती को दिखाया है।

जीडीपी वृद्धि

इसमें कहा गया है, 'आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) के अनुसार, अप्रैल में गतिविधियों में तेजी आई और शुरुआती अनुमान बताते हैं कि 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है।' आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण 'डायनेमिक फैक्टर मॉडल' का उपयोग करके, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े 27 महत्वपूर्ण (हाई फ्रीक्वेंसी) संकेतकों के सामान्य रुख को निकालकर किया गया।

सकल मांग और गांवों में गैर-खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च बढ़ने के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मंगलवार को जारी मई बुलेटिन में यह कहा गया है। बुलेटिन में प्रकाशित 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' पर एक लेख में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाली वैश्विक बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती को दिखाया है।

जीडीपी वृद्धि

इसमें कहा गया है, 'आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) के अनुसार, अप्रैल में गतिविधियों में तेजी आई और शुरुआती अनुमान बताते हैं कि 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत के आसपास रहने की उम्मीद है।' आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण 'डायनेमिक फैक्टर मॉडल' का उपयोग करके, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े 27 महत्वपूर्ण (हाई फ्रीक्वेंसी) संकेतकों के सामान्य रुख को निकालकर किया गया।

आवाजाही पर प्रतिबंध

फरवरी, 2020 में ईएआई को 100 रखा गया जबकि अप्रैल, 2020 में इसे शून्य कर दिया गया। इसका कारण अप्रैल महीना कोविड महामारी के कारण आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित था। सरकार 31 मई को मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान और वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय के अस्थायी अनुमान जारी करेगी।

गति का संकेत

भारत की वृद्धि दर 2023-24 की जून तिमाही में 8.2 प्रतिशत, सितंबर तिमाही में 8.1 प्रतिशत और दिसंबर तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही थी। लेख में कहा गया है कि जीएसटी संग्रह, बिजली खपत, माल ढुलाई जैसे 'हाई फ्रीक्वेंसी' संकेतक अप्रैल, 2024 में घरेलू मांग की स्थिति में निरंतर गति का संकेत देते हैं।

वाहन की बिक्री

टोल संग्रह इस साल अप्रैल में सालाना आधार पर 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोपहिया और तिपहिया खंड में मजबूत वृद्धि के कारण अप्रैल, 2024 में वाहन की बिक्री में सालाना आधार पर 25.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा की अगुवाई वाली टीम के लिखे लेख में कहा गया है, 'इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि भारत बहुप्रतीक्षित आर्थिक उड़ान भरने की दहलीज पर है। हाल के संकेत यह बताते हैं कि सकल मांग बढ़ रही है।'

मुद्रास्फीति

गैर-खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च से गांवों में व्यय में सुधार दिख रहा है। हेडलाइन (सकल) मुद्रास्फीति में इस साल अप्रैल में मामूली कमी आई। यह लक्ष्य के स्तर पर धीरे-धीरे पहुंचने की हमारी उम्मीदों के अनुरूप है। ईंधन के दाम में नरमी और मुख्य मुद्रास्फीति के नीचे आने तथा ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद खाद्य श्रेणी में सब्जियों, अनाज, दाल, मांस और मछली की कीमतें निकट अवधि में खुदरा मुद्रास्फीति को ऊंची और पांच प्रतिशत के करीब रख सकती हैं। यह अप्रैल में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अनुमान के अनुरूप है।

निजी निवेश

यह भी गौर करने लायक है कि घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पादों की मजबूत मांग से एफएमसीजी वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही। इस वृद्धि को 7.6 प्रतिशत की ग्रामीण वृद्धि से गति मिली। वहीं शहरी क्षेत्रों में वृद्धि 5.7 प्रतिशत थी। लेख में निजी निवेश के बारे में लिखा गया है कि सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की कमाई 2023-24 की दूसरी छमाही में कोष का प्रमुख स्रोत बना रहा।

राजस्व

लिस्टेड कंपनियों के अबतक घोषित वित्तीय परिणाम बताते हैं कि उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना और तिमाही आधार पर राजस्व में जो वृद्धि हासिल की, वह सर्वाधिक थी। लेख में लिखा गया है कि हेडलाइन (सकल) मुद्रास्फीति में इस साल अप्रैल में मामूली कमी आई।

ईंधन

यह हमारी उम्मीदों के अनुरूप है। ईंधन के दाम में नरमी और मुख्य मुद्रास्फीति के नीचे आने और ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंचने के बावजूद खाद्य श्रेणी में सब्जियों, अनाज, दाल, मांस और मछली की कीमतें निकट अवधि में खुदरा मुद्रास्फीति को ऊंची और पांच प्रतिशत के करीब रख सकती हैं। यह अप्रैल में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अनुमान के अनुरूप है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि बुलेटिन में लिखी बातें लेखकों के विचार हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

ई-कॉमर्स कंपनियों को शेयर्ड वेयरहाउस को कराना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑनलाइन सामानों की बिक्री और आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अब अपने शेयर्ड वेयरहाउस (साझा गोदाम) को भी जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खबर है कि जीएसटी के अधिकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के शेयर्ड वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने और रजिस्ट्रेशन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए व्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं। इन वेयरहाउसेज में कई स्प्लायर्स ग्राहकों तक सामानों की सप्लाई के लिए उनका भंडारण करते हैं। मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि जीएसटी नियमों के तहत कई सप्लायर्स को एक ही वेयरहाउस को अपने कारोबार के अतिरिक्त स्थान के तौर पर बताए जाने के बाद ऐसे वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने का मुद्दा सामने आया है।

जीएसटी के दायरे में आएगा शेयर्ड वेयरहाउस

मीडिया से बातचीत के दौरान मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम ऐसे वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से कई सप्लायर्स के सामनों को रखने के लिए बनाए गए वेयरहाउसेज के लिए शेयर्ड वर्कप्लेस पर जीएसटी नियमों को लागू किया जा सकता है या नहीं। जीएसटी कानून के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सामान की सप्लाई करने वाले अपने सामान को शेयर्ड वेयरहाउस में रख सकते हैं। हालांकि, सप्लायर्स को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वेयरहाउस को कारोबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में दिखाना जरूरी है।

जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा

अधिकारी ने कहा कि जब कई करदाता एक ही वेयरहाउस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जियो-टैग सभी के लिए एक ही पते को बताता है। यह जीएसटी अधिकारी को एक संकेत देता है कि कई करदाता एक ही स्थान पर स्थित हैं और यह एक संभावित धोखाधड़ी वाला रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि जिस वेयरहाउस में कई सप्लायर्स अपना सामान रखते हैं, उसे किसी एक सप्लायर्स की चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक जोखिम यह भी है कि जीएसटी अधिकारी ऐसी गड़बड़ी के लिए खुद ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है।

शेयर्ड वेयरहाउसेज के रजिस्ट्रेशन पर हो रही है चर्चा

ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से बनाए गए वेयरहाउसेज के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर इस महीने की शुरुआत में एक बैठक में केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों के बीच चर्चा की गई थी। अधिकारी ने कहा कि यह अभी चर्चा के स्तर पर है. ई-कॉमर्स वेयरहाउसेज के लिए शेयर्ड वर्कप्लेस पर जीएसटी नियम को लागू किया जा सकता है या नहीं, इस पर विधि समिति में चर्चा की जाएगी। इसके बाद इसे जीएसटी परिषद के समक्ष इसे रखा जाएगा. जीएसटी परिषद के तहत विधि समिति में केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं।

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

नॉर्थ ईस्ट के लोगों का पसंदीदा है रम दक्षिण भारत में बीयर का कल्चर है

...तो दिल्ली के लोगों को क्या है पसंद?

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत विविधताओं का देश है। किसी को पश्चिमी परिधान पसंद है तो कोई ठेठ देशी कपड़ों में ही जन्नत का आनंद लेते हैं। यही हालत खाने-पीने में भी है। कोई पिज्जा-बर्गर के पीछे पागल है तो किसी को मोमोज और चाउमीन ही चाहिए। दिल्ली के लोगों की नाक में लजीज छोले-भठूरे की खुशबू समा जाए तो वह सबकुछ छोड़ कर इसके पीछे पड़ जाएंगे। यही हालत अल्होकलिक बेवरेज (Alcohlic Beverage) में भी है। किसी राज्य के लोगों को रम (Rum) पसंद है तो कोई राज्य ब्रांडी (Brandy) का दीवाना है। कहीं बीयर (Beer) ही शराब के रूप में गटकी जाती है तो कहीं वाइन (Wine) के बिना काम ही नहीं चलता। आइए, आज इसी की बात करते हैं।

देश में सबसे ज्यादा क्या चलता है?

कन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाली शराब में व्हिस्की (Whisky) अव्वल है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भारत में अल्कोहलिक बेवरेज की कुल बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 63 फीसदी की है। इसी में इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और इंपोर्टेड लिकर (Imported Liquor) भी शामिल है। मतलब कि यह कह सकते हैं कि भारत में व्हिस्की अंगूरी को मात देती है।

इन राज्य के लोगों को तो रम चाहिए

इंटरनेशनल वाइन एंड स्पिरिट रीसर्च (International Wine & Spirit Research (IWSR) की साल 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में रम सबसे लोकप्रिय पेय है। वहीं तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में ब्रांडी ज्यादा लोकप्रिय है।

दक्षिण भारत में लिकर मतलब बीयर

आईडब्ल्यूएसआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब करीब पूरे दक्षिण भारत में लिकर (Liquor) का मतलब बीयर से लगाया जाता है। कोई भी अवसर हो, वहां के लोग बियर की बोतल खोलना या बीयर का केन खोलना ज्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि बीयर की पसंदगी की वजह वैयक्तिक हो। लेकिन पूरे इलाके में एक ही पेय बिकना कुछ तो संकेत देता ही है।

दिल्ली-मुंबई के लोगों को क्या है पसंद

आपको यह जान कर हैरानी होगी कि दिल्ली, मुंबई और पुणे के लोगों को अल्कोहलिक बेवरेज में वाइन पसंद है। दरअसल, इन तीनों महानगरों में ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं। साथ ही इन शहरों में ज्यादा पढ़े-लिखे और कल्चर्ड लोग भी रहते हैं। मतलब कि इन लोगों को वाइन का सिप लेना ज्यादा पसंद है। इसी श्रेणी में शैम्पेन (Champagne) जैसी अति प्रीमियम बेवरेज भी शामिल है।

शराब की हो रही है रिकॉर्ड बिक्री

शराब की बिक्री सदाबहार रहती है। कोरोना काल में याद कीजिए, जब शराब के दुकान खुले थे तो इसके सामने कई-कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। तभी तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में बनी विदेशी शराब (घ्इथ्) की बिक्री मात्रा के लिहाज से 14 प्रतिशत बढ़कर 38.5 करोड़ पेटी या केस तक पहुंच गई थी। बिक्री का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2019-20 (कोविड महामारी से पहले के स्तर) की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।

इस साल और बढ़ रही है बिक्री

सीआईएबीसी महानिदेशक विनोद गिरि बताते हैं कि अभी तक साल 2023-24 के आंकड़े की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जिस तरह के रुझान मिले हैं, उसे देखता हुए कहा जा रहा है कि इस साल भी अल्कोहलिक बेवरेज की बिक्री में आठ प्रतिशत तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ ही शराब की कुल बिक्री करीब 42 करोड़ पेटी तक पहुंच सकती है।

महंगी शराब की मांग तेजी से बढ़ रही है

विनोद गिरी बताते हैं कि इस समय महंगी शराब की बिक्री सस्ती शराब के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल के आंकड़े का हवाला देते हुए गिरी बताते हैं कि उस समय 1,000 रुपये प्रति 750 मिली से अधिक कीमत वाली प्रीमियम खंड की शराब की बिक्री 48 फीसदी बढ़ी। उसी साल आईएमएफएल की बिक्री में करीब 14 फीसदी फीसदी का इजाफा हुआ था।

एक पेटी में कितने लीटर

एक पेटी में नौ लीटर शराब होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बिकने वाली शराब में व्हिस्की अव्वल है और कुल बिक्री में इसकी 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कई राज्यों के लिए शराब रेवेन्यू जुटाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, यूपी समेत करीब एक दर्जन राज्यों ने पिछले साल शराब की कीमत में बढ़ोतरी की थी। इससे राज्यों की कमाई बढ़ाने में और मदद मिली है।

आईफोन की तरह अब भारत में ही बनेंगे गूगल पिक्सल फोन, जानिए किस कंपनी को मिला है प्रोजेक्ट?

नई दिल्ली। एजेंसी

ऐपल के आईफोन के बाद अब गूगल का पिक्सल स्मार्टफोन भी देसी होने जा रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को भारत में इस डिवाइस के निर्माण का प्रोजेक्ट मिला है। यह कदम सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पहल को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे ग्लोबल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम में भारत की स्थिति मजबूत होगी। ऐपल ने अपने प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा भारत ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद से भारत तेजी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनकर उभर रहा है। गूगल ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि भारत में पिक्सल फोन बनाना उसके एजेंडे में है। कंपनी ने तब कहा था कि वह भारत में पिक्सल 8 और इसके वर्जन को बनाने के लिए संभावित मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स और सप्लाई चेन ईकोसिस्टम से बात कर रही है।सरकार और इंडस्ट्री के सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि डिक्सन को भारत में पिक्सल बनाने के लिए चुना गया है। जल्द ही ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि गूगल भारत में उत्पादन का उपयोग घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने और संभावित रूप से निर्यात के लिए भी करना चाहता है। हालांकि इस बारे में डिक्सन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने अक्टूबर में इस बारे में बात की थी। उन्होंने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 'हमने क्ष्ददुर्तिर्ह्लें में स्थानीय स्तर पर पिक्सल स्मार्टफोन बनाने की योजना साझा की और उम्मीद है कि पहला डिवाइस 2024 में बाजार में आ जाएगा। हम भारत के डिजिटल विकास में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

कंपनी क्यों है उत्साहित

सूत्रों ने बताया कि गूगल एक वर्ष से अधिक समय से विभिन्न संभावित साझेदारों के साथ बातचीत कर रहा था। हाल ही में डिक्सन को इसके लिए चुना गया। भारत में स्मार्टफोन निर्माण में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके तहत उन्हें कई तरह के फायदे दिए जा रहे हैं। इससे गूगल भारत में स्मार्टफोन बनाने के लिए उत्साहित है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आरटीओ का नहीं लगाना होगा चक्कर, जान लीजिए सरकार का नया फैसला

नई दिल्ली।एजेंसी

ड्राइविंग लाइसेंस (ड्ढथ्) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव आगामी एक जून से लागू होने वाले हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या आरटीओ के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि यह बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को काफी हद तक सरल कर देगा।

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाना एक बोझिल प्रक्रिया

भारत में यदि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो अभी यह एक बोझिल प्रक्रिया है। क्योंकि आवेदक को कई फॉर्म भरने होते हैं। कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की ये जटिलताएं भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दायरे को बढ़ावा देती हैं। जो आखिरकार भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।

अब हो रहा है बदलाव

इन बोझिल प्रक्रिया से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफी सरल कर देंगे। ये बदलाव आगामी एक जून से देश भर में लागू हो जाएंगे।

क्या हो रहे हैं बदलाव

आवेदकों को अब सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंचने के बजाय अपने घर के पास के केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा। अभी डीएल लेने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में परीक्षा देने जाना पड़ता है। सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थानों को प्रमाणपत्र जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत होंगे।

बिना डीएल ड्राइविंग पड़ रहा है महंगा

बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना अब सख्त कर दिया गया है। अब ऐसा करने पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना तो लगता ही है, यदि चलाने वाला कोई नाबालिग है तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ संबंधित मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया में भी होगा बदलाव?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह पहले की तरह ही रहेगा। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट - https://parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि, वे मैनुअल प्रक्रिया के जरिए आवेदन जमा करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ पर भी जा सकते हैं। इसके लिए जन सेवा केंद्र की भी मदद ली जा सकती है।

भारतीयों ने विदेशों में खर्च किए 31.7 अरब डॉलर, जानिए किस चीज पर किया सबसे ज्यादा खर्चा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीयों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशों में रेकॉर्ड 31.7 अरब डॉलर खर्च किए जो पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी अधिक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह रकम 27.1 बिलियन डॉलर थी। टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स (TCS) लागू होने के बावजूद विदेशों में खर्च में यह बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि अक्टूबर 2023 में TCS लागू होने के बाद मासिक औसत खर्च में गिरावट आई है। रेमिटेंस के सालाना डेटा से पता चलता है कि भारतीयों ने वित्त वर्ष 24 में विदेश घूमने पर 17 अरब डॉलर खर्च किए। यह पिछले वर्ष के 13.6 अरब डॉलर से 24.5% अधिक है। महामारी की शुरुआत से पहले वित्त वर्ष 2020 में LRS के तहत खर्च में अंतरराष्ट्रीय यात्रा का हिस्सा 37% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 53.6ञ्च हो गया है। कोरोना काल में पाबंदियों के कारण वित्त वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर खर्च घटकर 3.2 अरब डॉलर रह गया था।दूसरी ओर, विदेश में शिक्षा के लिए जाने वाले रेमिटेंस का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2021 में, शिक्षा के लिए रेमिटेंस 30% था। वित्त वर्ष 2022 में यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद यह हिस्सा गिरकर 26% रह गया। वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा पर खर्च पिछले वर्ष के 5.2 अरब डॉलर से घटकर 3.4 अरब डॉलर रह गया। इस कारण कुल खर्च का हिस्सा गिरकर 12ञ्च रह गया। वित्त वर्ष 2024 में, विदेश में पढ़ाई पर खर्च लगभग 3.5 अरब डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि यात्रा पर खर्च बढ़ गया। फीस पर कम खर्च के कारण विदेश में पढ़ाई अब विदेशी मुद्रा खर्च में दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी नहीं रह गई है। भारतीयों ने फीस की तुलना में विदेश में रिश्तेदारों के रख-रखाव पर ज्यादा खर्च किया। इस मद में 4.6 अरब डॉलर खर्च हुए।

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

समाचार विशेष

प्रति बुधवार
इंदौर, 22 मई 2024 से 28 मई 2024

सफलता के लिए शेयर बाजार में धन के साथ ही अच्छे लोगों के साथ अपने समय का निवेश भी करें

राजकुमार जैन
स्वतंत्र लेखक एवं विचारक

कदली, सीप, भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन।।

रहीम कहते हैं कि स्वाति-नक्षत्र की वर्षा की बूँद तो एक ही हैं, पर उसका गुण संगति के अनुसार बदलता है। कदली में पड़ने से उस बूँद की कपूर बन जाती है, अगर वह सीप में पड़ी तो मोती बन जाती है तथा साँप के मुँह में गिरने से उसी बूँद का विष बन जाता है।

हम मानव एक समाज में रहते हैं और हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते। अपने जीवन काल मे हम प्रतिदिन कई लोगो से मिलते है और इस मिलन का असर हमेशा हमारे व्यक्तित्व और हमारे विचारों पर पड़ता जरूर है।

जब हम किसी व्यक्ति या समूह से घुलते-मिलते है तो वह हमारे व्यक्तित्व पर अपना असर छोड जाता है। उनके विचार हमारी सोच को प्रभावित करते है, उसके स्वभाव अनुसार हमारे स्वभाव मे परिवर्तन आता है, समान आदते विकसित होने लगती है। यह सब संगति का स्वाभाविक असर है।

अच्छी सोच वाले व्यक्ति हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति आपको पीछे खींच लेंगे। दूसरों के व्यक्तित्व का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन निरंतर पड़ता रहता है। हमारे जीवन में उन्नति और कल्याण हमारी संगति पर निर्भर करता है। अच्छी संगत से ही मनुष्य के सच्चरित्र का निर्माण होता है और बिना चरित्र निर्माण के हम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते।

मनुष्य के जीवन में उसके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो किस तरह अपनी बात रखता है, किस शैली मे अपने विचार व्यक्त करता है, दूसरों से कैसा व्यवहार करता है, विपरीत परिस्थितियो मे किस तरह से निर्णय लेता है, यह सब उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण मे उसकी रोज़मर्रा की संगति और उसके ईद के ईर्द-गिर्द रहने वाले लोगों का गहरा योगदान होता है। अच्छी संगति में रहने से व्यक्तित्व का निखार होता है तो बुरी संगति जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए इस बात पर हमेशा विचार करते रहना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

हमारा व्यक्तित्व विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का एक विशिष्ट स्वरूप है जो हमको दूसरों से अलग बनाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्म से ही उत्पन्न होता है, जो बीतते समय के साथ निरंतर परिष्कृत होता जाता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके व्यवहार, दृष्टिकोण और विचारो से पता चलता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इसमें अंतर्निहित और अर्जित दोनों तरह की व्यवहारिक विशेषताएं शामिल हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती हैं।

जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हमें अलग-अलग तरह के लोग मिलते हैं जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमारी आदतों, क्षमताओ और स्वभाव पर पड़ता है जो जीवन में हमें आगे बढ़ने में मदद करता हैं। हमारा जुड़ाव ऐसे लोगो से सहज ही हो जाता है जो समान चुनौतियों और अवसरों को साझा करते हैं। जिनके व्यक्तित्व और संगति समान जड़ों से जुड़े होते है। जो आपसी व्यवहार मे समान विचारधारा रखते है। वर्तमान समय मे उपयोग की जा रही तकनीक जिसमें कंप्यूटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन जैसे उपकरण शामिल हैं, से एकदूसरे से संपर्क स्थापित करना बहुत सरल हो गया है और अब हम पहले की बनिस्बत ज्यादा लोगों से शीघ्रता से संपर्क स्थापित कर पा रहे हैं। यह कहना गलत नही होगा कि आज हर कोई एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, और आज हम कई तरह के विषयों को देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं जो एक दूसरे के व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव छोडते है। मनुष्य जो करता है या कहता है इसका प्रभाव न सिर्फ उन आस-पास रहने वाले लोगों पर होता है, बल्कि अन्य दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव सकारत्मक या नकारात्मक दोनों तरह का हो सकता है इसलिए इससे सतर्क होने की जरूरत है। हम कुछ लोगों के साथ सिर्फ समय बिताते हैं लेकिन कुछ लोगों के साथ हम अपने समय का निवेश करते हैं। उचित लोगों के साथ अपने समय का निवेश करना ही सफलता की असली चाबी है।

FTA वाले देशों का जलवा! जमकर हो रहा भारत से व्यापार, देखिए ये आंकड़े

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वाले देशों से माल का आयात वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच करीब 38 प्रतिशत बढ़कर 187.92 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) भागीदारों को देश का निर्यात 2018-19 में 107.20 अरब अमेरिकी डॉलर से 2023-24 में 14.48 प्रतिशत बढ़कर 122.72 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।

38 प्रतिशत बढ़ा आयात

शोध संस्थान ने कहा, ''भारत का आयात वित्त वर्ष 2018-19 से 2023-24 के बीच करीब 37.97 प्रतिशत बढ़कर 187.92 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह वृद्धि भारत की वैश्विक व्यापार गतिशीलता पर मुक्त व्यापार समझौतों के महत्वपूर्ण तथा विविध प्रभाव को दर्शाती है।'' आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का निर्यात 2023-24 में 18.25 प्रतिशत बढ़कर 35.63 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2018-19 में यह 30.13 अरब अमेरिकी डॉलर था। आयात वित्त वर्ष 2018-19 में 29.79 अरब अमेरिकी डॉलर से 61.21 प्रतिशत बढ़कर 48.02 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एफटीए मई 2022 में लागू हुआ था।

इन देशों से भी बढ़ा आयात-निर्यात

इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जापान, 10 देशों वाले दक्षिणपूर्व एशियाई गुट आसियान और दक्षिण कोरिया के साथ भी एफटीए के बाद निर्यात और आयात में बढ़ोतरी हुई है। भारत विश्व व्यापार में 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निर्यात में विश्व स्तर पर 17वें स्थान पर है। आयात के मोर्चे पर वैश्विक व्यापार में 2.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश आठवें स्थान पर है।

23-24 में गिरा व्यापारिक निर्यात

वित्त वर्ष 2023-24 में हालांकि भारत का व्यापारिक निर्यात 3.11 प्रतिशत गिरकर 437.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया और आयात भी 5.4 प्रतिशत घटकर 677.2 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। अजय श्रीवास्तव जीटीआरआई के सह-संस्थापक हैं। वह एक भारतीय व्यापार सेवा अधिकारी थे। मार्च 2022 में वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लिया। उनके पास व्यापार नीति निर्माण, डब्ल्यूटीओ और एफटीए वार्ता का अनुभव है।

भारत में अगले 5 से 10 साल में दोगुना हो जाएगी जिंक की मांग

नई दिल्ली। एजेंसी

स्टील सहित इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी निवेश से अगले 5 से 10 साल में देश में जस्ता की मांग दोगुना हो जाने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ ने यह बात कही। भारत में जिंक की मांग काफी हद तक स्टील मार्केट की बढ़ोतरी पर निर्भर करती है, क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात (Steel) को जंग से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक की मांग दोगुनी होने से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को फायदा होगा। यह जस्ता, सीसा, चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और संसाधन उत्पादक है। यह वेदांत लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

जस्ता के लिए मांग दोगुनी होने की उम्मीद

अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ के वैश्विक निदेशक मार्टिन वान लियूवेन ने कहा, मुझे अगले 5 से 10 साल में जस्ता के लिए मांग दोगुनी होने की उम्मीद है। भारत में प्राथमिक और परिष्कृत जस्ता बाजार वर्तमान में 800 से 1,000 टन सालाना के करीब है और हम भारत में जो विकास देख रहे हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें बढ़ोतरी का एक शानदार अवसर है।

800 से 1,000 टन प्रति वर्ष मांग

उन्होंने कहा, हम अतिरिक्त इस्पात क्षमता में भारी निवेश देख रहे हैं और इस्पात को अभी भी 'गैल्वेनाइज्ड कोटिंग्स' द्वारा संरक्षित करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि नई गैल्वनाइजिंग लाइन के लिए बहुत सारी योजनाएं और निवेश चल रहे हैं। इसलिए मुझे भारत में जस्ता की मांग बढ़ने की उम्मीद है. भारत में जिंक की मौजूदा मांग 800 से 1,000 टन प्रति वर्ष है।

उन्होंने कहा कि भारत में जस्ता उपयोगकर्ता बहुत कम हैं।देश में इसकी प्रति व्यक्ति खपत लगभग आधा किलोग्राम है और यह वैश्विक औसत से काफी कम है उन्होंने कहा, अगर आप भारत में जस्ता के उपयोग को देखें, तो यह प्रति व्यक्ति लगभग आधा किलोग्राम है। वहीं इसका वैश्विक औसत 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। वहीं दक्षिण कोरिया, यूरोप, अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह 6 से 7 किलोग्राम तक जा सकता है। चालू कैलेंडर साल के लिए जस्ता क्षेत्र के आउटलुक पर उन्होंने कहा कि दुनिया ग्रीन ऊर्जा (Green Energy) की ओर स्थानांतरित हो रही है। सोलर फोटोवोल्टिक (PV) में मजबूत बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसे में 2024 जस्ता क्षेत्र के लिए काफी बड़ा अवसर है।

FSSAI की क्लीन चिट

भारतीय मसालों में नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

फूड रेगुलेटर FSSAI ने भारत के बाजारों से मसालों के सैंपल लेकर की गई जांच के बाद दावा किया है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide) की मात्रा नहीं पाई गई है। इन मसालों में एवरेस्ट और एमडीएच भी शामिल हैं, जिन पर हॉन्गकॉन्ग ने यह कहते हुए बैन लगा दिया था कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा मिली है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। FSSAI ने 22 अप्रैल को देशभर से नमूने जुटाने शुरू किए। इसके तहत, एवरेस्ट और एमडीएच मसालों के 34 नमूने जमा किए गए। विशेष रूप से, महाराष्ट्र और गुजरात में एवरेस्ट के 9 नमूने और दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से एमडीएच के 25 नमूनों का विश्लेषण किया गया।फूड रेगुलेटर ने कहा है कि नमी की मात्रा, कीट, एफ्लाटॉक्सिन, कीटनाशक और अन्य चीजों की जांच की गई। खास तौर पर एथिलीन ऑक्साइड के लिए भी जांच की गई। 34 नमूनों में से 28 की लैब रिपोर्ट मिल चुकी है। इन सभी नमूनों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा नहीं मिली है। इसी के साथ इएएंड ने भारतीय बाजार में उपलब्ध मसालों को सुरक्षित बताया है। दरअसल, एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल मसालों को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यदि इसकी मात्रा सुरक्षित स्तर से अधिक हो तो इससे कैंसर समेत अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है।

क्यों मचा है हंगामा

हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर ने एवरेस्ट और एमडीएच कंपनियों के कुछ उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल समेत कई देशों ने भारतीय मसालों को निगरानी लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार और मसाला बोर्ड हरकत में आया है। हॉन्गकॉन्ग और सिंगापुर को भेजे जाने वाले मसालों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक भी सोवेनियर के तौर पर मसाला ले जाना पसंद करते हैं।

कब ज्योतिष शास्त्र से मिलता है लाभ और कब भविष्यवाणी हो जाती है निष्फल

कठिनाइयों के क्षणों में, विपत्ति की घड़ियों में या ऐसे समय में जब व्यक्ति के पुरुषार्थ का जोर नहीं चलता, तब व्यक्ति सीधे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर में जाता है या फिर सीधे ज्योतिषी की शरण जाकर अपने दुःख-दर्द की फरियाद करता है। ईश्वर तो बोलते नहीं पर ईश्वर की वाणी ज्योतिषी के मुखारबिंद से प्रकट होती है।

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

ज्योतिष शास्त्र के अन्तर्गत जन्मकुण्डली, हस्तरेखा, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से दैवीय संकेतों को पड़कर भविष्यवाणी की जाती है, अतः भविष्य दर्शन के लिए ज्योतिषी की शरण में आने वाले को दैवीय शक्ति का आभार मानना चाहिए।

सृष्टि का नियम है कि दैवज्ञ, गुरू आदि के पास अन्तर्मन से समर्पित होकर आने वाला व्यक्ति सब कुछ पाता है। जब तक सामने वाला समर्पित भाव, विनम्र और कृतज्ञता का भाव नहीं रखता है, दैवीय शक्ति या मां सरस्वती की कृपा नहीं होती।

ज्योतिषी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको ज्योतिष शास्त्र अथवा ज्योतिषी पर विश्वास नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जन्मकुण्डली आदि का विचार नहीं करवाना चाहिए।

ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं करते, ग्रह-नक्षत्र स्वयं बोलते हैं। ईश्वर के पश्चात् सिद्धान्त, संहिता, होरा, त्रिस्कन्ध का ज्ञाता विद्वान ज्योतिषी ही वह पहला व्यक्ति है जो आपके बारे में सही जानकारी रखता है।

ज्योतिष शास्त्र की नियमावली अनुसार हंसी-दिल्लगी व मनोविनोद से पूछे गए प्रश्नों का जवाब एवं अपात्र व्यक्ति को इस विद्या का उपेदश नहीं देना चाहिए, कुपात्र से बहस नहीं करनी चाहिए, बिना पूछे किसी को भी ज्योतिषीय सलाह नहीं देनी चाहिए, इससे शास्त्र की मर्यादा कम होती है। जब तक जिज्ञासु सज्जन फल, पुष्प, नारियल और दक्षिणा के साथ यथाशक्ति विद्वान दैवज्ञ का सम्मान न करे तब तक दैवज्ञ इस दिव्य विद्या का उपदेश न करे। प्रकृति का शाश्वत नियम है जो खाली हाथ आता है वह खाली हाथ ही जाता है।

व्यक्ति को अपने पूर्वजन्मों में अर्जित कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख प्राप्त होता है, ग्रह नक्षत्र केवल सूचना देते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति और व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध को पढ़ने का ज्योतिष शास्त्र मात्र एक माध्यम है। केवलं ग्रह नक्षत्रं न करोति शुभाशुभं। सर्वमात्रकृतं कर्मं लोकवादो ग्रहा इति।।

आने वाला है बुढ़वा मंगल, इन राशियों पर बरसेगी हनुमान जी की विशेष कृपा

भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना करने के लिए मंगलवार का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है. उसमें भी बुढ़वा मंगल को तो विशेष दर्जा दिया गया है. ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार कहते हैं. इस दिन हनुमान जी के वरद रूप की पूजा की जाती है. बुढ़वा मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से हर दुख-दर्द, दोष और भय दूर हो जाता है. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. इस साल तो बुढ़वा मंगल के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं जो विशेष फलदायी होंगे.

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

कब-कब पड़ रहा बुढ़वा मंगल?

इस साल 24 मई से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 24 जून को समाप्त होगा. इस दौरान 4 बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगलवार पड़ेंगे. पहला बुढ़वा मंगल 28 मई 2024 को पड़ेगा. इसके बाद दूसरा बुढ़वा मंगल 4 जून, तीसरा बुढ़वा मंगल 11 जून और चौथा बुढ़वा मंगल 18 जून 2024 को पड़ेगा.

28 मई पहला बुढ़वा मंगल पर बन रहे शुभ योग

28 मई को पहला बुढ़वा मंगल पर मालव्य राजयोग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं जो 3 राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होंगे. इन जातकों को हनुमान जी की कृपा से अपार सुख-समृद्धि, लंबी आयु और यशपूर्ण जीवन मिलेगा.

मेष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि

किन राशियों के लिए शुभ होता है मोती रत्न?

जान लें इससे जुड़े नियम, वरना झेलना पड़ सकता है अशुभ प्रभाव

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

ज्योतिष शास्त्र में रत्न बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. ये रत्न व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रहों की शुद्धता को बढ़ाने का काम करते हैं. कोई भी रत्न धारण करने से पहले उनके नियमों, शुभ-अशुभ प्रभाव के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है. किसी को भी रत्न धारण करने से पहले विद्वानों से सलाह जरूर लेनी चाहिए. इसी के चलते आज हम आपको मोटी रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं. हम आपको बताएंगे कि मोती किस राशि के लिए शुभ होता है, किसके लिए अशुभ और इसको धारण करने के नियम क्या हैं.

किस ग्रह से संबंध रखता है मोती?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोती का संबंध चंद्रमा से होता है. जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनको मोती पहनने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि जिन लोगों के मन में नेगेटिव विचार आते हैं उनके लिए भी मोती रत्न फायदेमंद होता है.

मोती पहनने के फायदे

जिन लोगों को काफी गुस्सा आता है उनके लिए मोती पहनना फायदेमंद होता है.

स्किन से जुड़ी बीमारियों से राहत और मानसिक शांति पाने के लिए मोती रत्न पहनना लाभकारी साबित होता है.

मोती रत्न धारण करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास और मनोबल में बढ़ोतरी होती है.

किन राशि के लिए शुभ है मोती?

मोती रत्न धारण करने से पहले कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का पता होना बेहद आवश्यक है. कुछ राशियों के लिए मोती पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को मोती शुभ परिणाम देता है.

कब और कैसे धारण करें मोती?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार और पूर्णिमा के दिन मोती रत्न धारण करना शुभ माना जाता है. वहीं, 7-8 रत्ती का मोती रत्न धारण करना चाहिए. इसको धारण करने के लिए आप मोती को गंगाजल या फिर गाय के कच्चे दूध में 10 मिनट भिगो दें और फिर पहनें. मोती धारण करने से पहले ॐ चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

किस अंगुली में पहनें मोती?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हों उसकी कनिष्ठिका या कहा जाए छोटी अंगुली में मोती धारण करना शुभ परिणाम देता है. मोती को किस धातु में पहनना चाहिए इसके लिए विद्वानों और ज्योतिषियों की सलाह लेनी चाहिए. वैसे मोती को अक्सर चांदी में धारण करना चाहिए. आपको ध्यान रखना चाहिए कि नीलम या गोमेद के साथ कभी भी मोती को धारण न करें.

सच में चाहिए छप्पर फाड़ धन? केवल गुरुवार को करना होगा ये काम

पंडित कपिल पाराशर
बनारस वाले ज्योतिष आचार्य वास्तु विशेषज्ञ

सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवी-देवता को समर्पित है, साथ ही दिनों का ग्रहों से भी संबंध है. गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन इन दोनों की पूजा-आराधना करने से बहुत लाभ होता है. जीवन में सुख-सौभाग्य बढ़ता है. महिलाएं वैवाहिक सुख पाने के लिए गुरुवार का व्रत रखती हैं. साथ ही भगवान विष्णु की कृपा अपार धन-दौलत, ऐश्वर्य और सुख देती है. गुरुवार व्रत और पूजा करने से अविवाहित लड़कियों का जल्द विवाह हो जाता है. यदि आप भी धन-दौलत, मनचाही सफलता, यश, सुख चाहते हैं तो गुरुवार के दिन ये उपाय जरूर करें.

धन प्राप्ति के गुरुवार के उपाय

जीवन में अक्सर आर्थिक तंगी बनी रहती है तो इससे निजात पाने के लिए गुरुवार को तुलसी के पत्ते का यह उपाय कर लें. इसके लिए गुरुवार की सुबह जल्दी स्नान करके भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. फिर हाथ में तुलसी दल लेकर 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः' मंत्र का जाप करें और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित कर दें. कम से कम 7 से 11 गुरुवार तक यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से निजात मिल सकती है.

हर गुरुवार को तुलसी जी की पूजा करें. भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं. इसके साथ ही गुरुवार सुबह तुलसी के पौधे में कच्चा दूध और गंगाजल मिलाकर अर्घ्य दें. फिर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें. फिर शाम को तुलसी के सामने शुद्ध घी के दीये जलाकर उनकी आरती करें. यह उपाय बहुत लाभ देगा और आपके घर में तेजी से धन की आवक बढ़ेगी.

गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी की मंजरी अर्पित करें. फिर पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें. यह उपाय करते ही तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा.

गुरुवार को तुलसी की जड़ को गंगाजल से धोकर पीले कपड़े में बांध लें. फिर उसे तिजोरी में रख लें या घर के मुख्य द्वार पर बांध दें. यह उपाय घर में सकारात्मकता लाता है और धन-दौलत बढ़ाता है.

मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रही बरकत? आजमाएं ये सरल उपाय

- गुरुवार के दिन आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, इसकी रोटी बनाएं और गाय को खिला दें. ये उपाय करने से आपके जीवन की कई मुश्किलें तो दूर होंगी ही साथ में घर में पैसा भी टिकेगा और खर्चों में भी कमी आएगी.
- हिन्दू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आप धन की देवी की पूजा करें और लाल फूल अर्पित करें. इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगी.
- धन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पत्ते पर राम लिखें और हनुमान मंदिर में रख कर आजाएं. साथ ही हनुमान जी को बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं. इससे हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न होंगे.
- धनलाभ के लिए आप नियमित रूप से विधि विधान से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इससे मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होंगी ही साथ ही धनलाभ के भी प्रबल संयोग बनेंगे.
- शुक्रवार के दिन अशोक वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर के धन वाले स्थान या फिर तिजोरी में रख दें. इससे घर में धन की कमी नहीं होती साथ ही धन का आगमन होता रहता है.

विकसित भारत की दिशा में बढ़े कदम, बेहतर हो रही जिंदगी

पहले से कहीं अधिक भारतीय कर रहे विमान यात्रा

नई दिल्ली। एजेंसी

वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के साथ ही पूरा देश प्रयास कर रहा है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं, देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। आमदनी बढ़ रही है। लोग मूलभूत जरूरतों के अलावा घूमने फिरने पर भी जमकर खर्च कर रहे हैं। हाल ही में किए गए दो अध्ययनों से इसकी पुष्टि हुई है। द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारतीय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष हो सकती है, वहीं इस अवधि में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक होगी। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली तिमाही में नौ करोड़ 70 लाख लोगों ने विमान यात्रा की है।

भारतीय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी

द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2050 तक भारतीय महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 80 वर्ष तक पहुंच सकती है। इस दौरान भारतीय पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष से अधिक होगी। जीवन प्रत्याशा किसी समूह की औसत जीवन अवधि होती है। भारत में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्वस्थ जीवन प्रत्याशा 65 वर्ष से अधिक होने का अनुमान है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य उस औसत उम्र है जिस उम्र तक स्वस्थ रहने की उम्मीद की जा सकती है।

द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन के अनुसार, 2022 और 2050 के बीच दुनिया भर में पुरुषों में जीवन प्रत्याशा में लगभग पांच साल और महिलाओं में चार साल से अधिक सुधार होने का अनुमान है। दुनिया भर में स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, आने वाले वर्षों में 2.6 साल बढ़ जाएगी - 2022 में 64.8 साल से बढ़कर 2050 में 67.4 साल हो जाएगी।

शोधकर्ताओं के अनुसार दिल के रोगों, कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियों, मातृ, नवजात और पोषण संबंधी बीमारियों से बचाव के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का अनुमान है। गौरतलब है कि भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में 70.8 वर्ष थी। अमेरिका के वाशिंगटन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फार हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (आइएचएमई) सहयोग से ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज (जीबीडी) अध्ययन किया गया है।

पहले से कहीं अधिक भारतीय कर रहे विमान यात्रा

अंतरराष्ट्रीय यात्रा हो या घरेलू पहले से कहीं अधिक भारतीय यात्रा कर रहे हैं। 2024 के पहले तीन महीनों में नौ करोड़ 70 लाख भारतीयों ने विमान यात्रा की। मास्टरकार्ड इकोनामिक्स इंस्टीट्यूट (एमईआइ) द्वारा किए गए अध्ययन ''ट्रैवल ट्रेंड्स 2024: ब्रेकिंग बाउंड्रीज'' की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले तीन महीनों में नौ करोड़ 70 लाख यात्रियों ने भारतीय हवाईअड्डों से यात्रा की। घरेलू हवाई यात्री यातायात 2019 के स्तर से 21 प्रतिशत अधिक बढ़ा, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रा में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारतीय आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं

रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में जापान की यात्राओं में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वियतनाम की यात्राओं में 248 प्रतिशत की वृद्धि और महंगे अमेरिकी डालर के बावजूद अमेरिका की यात्राओं में 59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई हुई है। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार एम्स्टर्डम, सिंगापुर, लंदन, फ्रैंकफर्ट और मेलबर्न शीर्ष पांच पसंदीदा गंतव्य हैं जहां भारतीय यात्री इस गर्मी (जून-अगस्त 2024) में जा रहे हैं। 2020 में लांच किया गया मास्टरकार्ड इकोनामिक्स इंस्टीट्यूट उपभोक्ता के नजरिए से व्यापक आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करता है।

विमानन क्षेत्र के विकास का पावर हाउस बनेगा

भारत भारत विमानन क्षेत्र के विकास का पावर हाउस बनेगा। एक रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है। नीदरलैंड स्थित आइएनजी बैंक एनवी ने कहा कि एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एअर इंडिया नए विमानों के लिए ऐतिहासिक रूप से बड़ा आर्डर दिया है। इसमें कहा गया है, भारत कई नए हवाईअड्डे खोलने की योजना बना रहा है।

ATCM और CEP की 26वीं बैठक में भारत की मेजबानी में होगी

अंटार्कटिका में पर्यटन विकास पर चर्चा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत 46वीं अंटार्कटिक (दक्षिणी ध्रुव प्रदेश) संधि परामर्शदात्री बैठक (ऊिण) और पर्यावरण संरक्षण समिति (एिं) की 26वीं बैठक की कोच्ची में मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेतन में पहली बार अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने पर पहली बार विशेष रूप से चर्चा होगी।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस सम्मेलन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भाग लिया। 20 मई से केरल के कोच्चि में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा और अंटार्कटिक संधि सचिवालय इन बैठकों को कर रहे हैं, यह सम्मेलन 30 मई तक चलेगा। इस सभा में लगभग 40 राष्ट्र के 350 से अधिक प्रतिभागी हैं।

अंटार्कटिका आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

दरअसल भारत अंटार्कटिक संधि प्रणाली का एक प्रतिबद्ध सदस्य होने के नाते, अंटार्कटिका में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों और महाद्वीप के नाजुक पर्यावरण पर उनके प्रभाव से निपटने की तत्काल आवश्यकता महसूस करता है। पिछले कुछ वर्षों में अंटार्कटिका आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, पर्यटन एक प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिससे यह महत्वपूर्ण हो गया है कि इस अनूठे और प्राचीन क्षेत्र में टिकाऊ व उत्तरदायित्वपूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नियम बनाए जाएं।

भारत अंटार्कटिक संधि प्रणाली का एक प्रतिबद्ध सदस्य

बता दें, भारत अंटार्कटिक संधि का सलाहकार पक्ष रहा है। भारत अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अन्वेषण और पर्यावरण संरक्षण को अन्य 28 सलाहकार पक्षों के साथ, संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पास एटीसीएम में प्रशासन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और लॉजिस्टिकल सहयोग के मामलों में लिए गए निर्णयों और प्रस्तावों पर प्रस्ताव रखने और मतदान करने का अधिकार है। इसके अलावा, यह अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, वैज्ञानिक कार्यक्रम और लॉजिस्टिक संबंधी संचालन कर सकता है, पर्यावरण नियमों को लागू कर सकता है और अंटार्कटिक संधि के सदस्यों द्वारा साझा किए गए वैज्ञानिक डेटा और शोध निष्कर्षों तक पहुंच सकता है।

हर साल आयोजित होती हैं बैठकें

अंटार्कटिक को लेकर वर्ष 1959 में संधि हुई थी, जिसमें 56 देश सम्मिलित हैं। इसके प्रावधानों के अनुसार एटीसीएम और सीईपी उच्च स्तरीय वैश्विक वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में, अंटार्कटिक संधि के सदस्य देश अंटार्कटिका के विज्ञान, नीति, शासन, प्रबंधन, संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सीईपी की स्थापना 1991 में अंटार्कटिक संधि (मैड्रिड प्रोटोकॉल) के पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत की गई थी। सीईपी (CEP) अंटार्कटिका में पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा पर एटीसीएम को सलाह देता है।

सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड पेश :पोटेंशियल ग्रोथ का लाभ उठाने का प्रभावी तरीका

एनएफओ 17 मई 2024 को खुलेगा और 31 मई 2024 को बंद होगा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक प्रतिष्ठित निवेश प्रबंधन फर्म, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड यानी विशेष अवसर निधि (एसओएफ) के लॉन्च की घोषणा करते हुए रोमांचित है। इस अनूठे फंड को बाजार के अवसरों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य कम मूल्य वाले या उपेक्षित अवसरों के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि दर्ज करना है। इस फंड के खुलने की तारीख 17 मई, 2024 है और 31 मई, 2024 को क्लोज होगा। सैमको म्यूचुअल फंड का स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड एक डिस्रप्शन स्ट्रेटेजी पर तैयार किया गया है जिसमें डिजिटलीकरण, इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग, स्पिन ऑफ और कॉर्पोरेट एक्शंस, सुधार-नियामक, सरकार, अंडरवैल्यूड होल्डिंग कंपनियां, प्रीमियमाइजेशन, ट्रेंड्स सस्टेनेबल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन, संगठित बदलाव, नए और उभरते क्षेत्र सहित 10 अलग-अलग उप-रणनीतियां शामिल हैं। इस मॉडल में 10 उप-रणनीतियां निवेशकों के लिए संभावित विकास और मूल्य की तलाश करने के लिए जोखिम और विशेष परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, विविध प्रकार के निवेश विचारों को सामने लाते हुए व्यवस्थित दृष्टिकोण को सक्षम बनाती हैं। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी फंड की एक प्रमुख विशेषता है, जो इसे सभी क्षेत्रों और विषयों में निर्बाध रूप से घूमने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह उभरते रुझानों को पकड़ने और बाजार की बदलती गतिशीलता को भुनाने के लिए तैयार है।

डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीज तक का इलाज कराना होगा सस्ता, सरकार ने 41 दवाओं की कीमतें घटाई

नई दिल्ली। एजेंसी

यूं तो दुनिया में डायबिटीज के रोगी चीन में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन भारत भी कोई पीछे नहीं है। साल 2021 का आंकड़ा बताता है कि भारत में उस सयम 7.41 करोड़ शुगर पेशेंट्स थे। शुगर पेशेंट्स के साथ-साथ हार्ट पेशेंट, लीवर की बीमारी से जूझ रहे पेशेंट्स को अब थोड़ी आसानी होगी। आसानी इसलिए, क्योंकि इन बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और छह फॉर्मूलेशन की कीमतें कम कर दी हैं। यह फैसला केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी का है।

कई दवाएं होंगी सस्ती

फार्मास्यूटिकल्स विभाग और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, एंटासिड, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स उन दवाओं में से हैं जो सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ ही सभी फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न दवाओं की कम कीमत की जानकारी तत्काल प्रभाव से डीलरों और स्टॉकिस्टों को दें।

143वीं बैठक में लिया गया यह फैसला

एनपीपीए की 143वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक दवाओं की कीमत जनता के लिए सस्ती रहे।

भारत में शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा

भारत दुनिया में डाइबिटीज के सबसे अधिक मामलों वाले देशों में से एक है। यहां 10 करोड़ से अधिक मधुमेह रोगी हैं, जिन्हें दवा की कीमत में कटौती से लाभ होने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 1 अप्रैल से प्रभावी, 923 अनुसूचित दवा फॉर्मूलेशन के लिए अपनी वार्षिक संशोधित कीमतें और 65 फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित खुदरा कीमतें जारी की थीं।

प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करना प्राथमिकता - निगम आयुक्त

नई तकनीक देखने दिल्ली जाएंगे अधिकारी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश में स्वच्छता के लिए लगातार 7 बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले इंदौर शहर में प्लास्टिक वेस्ट का प्रबंधन नगर पालिक निगम की प्राथमिकता है। इसे बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कियाजाएगा। इसके लिए देश के पहले प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी आधारित आयोजन में नगर निगम के अधिकारी भी भाग लेने दिल्ली जाएगें। यह बात इंदौर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने जीसीपीआरएस के इंदौर रोड शो में कही। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक रिसाईकलिंग के नए तरीके और तकनीक से हम इंदौर के वेस्ट मैनेजमेंट को पहले से बेहतर कर सकेगें। इसके लिए आम जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों और प्रशासन सहित सभी एक दिशा में काम करते रहना होगा। देश में पहली बार प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन Global Conclave on Plastics Recycling and Sustainability (GCPRS) को 4 से 7 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन को प्रमोट करने के लिए इंदौर में रोड शो किया गया।

इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष और मप्र शासन के शहरी विकास मंत्रालय कीराज्य स्तरीय सलाहकार समिति (पीडब्लूएम) के सदस्य श्री सचिन बंसल ने बताया कि आल इंडिया प्लास्टिक मैन्यूफैक्चारिंग एसोसिएशन मुंबई के द्वारा नई दिल्ली प्रगति मैदान में होने वाले इस आयोजन में प्लास्टिक रिसाईकलिंग पर दुनिया की बेहतर तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इसमें इंदौर के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए रोड शो होटल सयाजी में किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि इंदौर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने सीजीपीआरएस के आयोजन में इंदौर से अधिकारियों को भेजने और स्वंय भी शामिल होने की बात कही है। श्री बंसल ने शहर में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंदौर निगम आयुक्त से स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक रिसाईकलिंग उद्योगों के अनुभवो का लाभ लेने का भी आग्रह किया। मुंबई से आए जीसीपीआएस के श्री सिद्धार्थ शाह ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक उद्योगों की संस्था AIPMA ने भारतीय प्लास्टिक उद्योगमें सिद्ध रीसाइक्लिंग और स्थिरता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी - जीसीपीआरएस के आयोजन को कर रही है। वर्तमान में भारत के 3.4 मिलियन टन (एमटी) प्लास्टिक कचरे में से केवल 60% का ही रिसाईकलिंग किया जाता है। इसे बढाने,प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नए उपकरणों, मशीनों और तकनीक का प्रदर्शन आयोजन में किया जाएगा। इसका लाभ पॉलीमरइंडस्ट्रीज को बडे रूप में मिलेगा। आयोजन में मप्र प्लास्टिक रिप्रोसेस ग्रेन्युअल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गुरुवीर सिंह, सचिवश्री रूचिल जैन, आईपीपीएफ के सचिव श्री अंकित भरूका, वरिष्ठ उद्योगपति श्री हितेश मेहता, श्री आरके माहेश्वरी, श्री ब्रजेश गांधी, श्री संदीप ठाकुर, श्री विशाल सोनी सहित बडी संख्या में उद्योगपति मौजूद थे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।